

Participants : [Singh Shri Rajiv Ranjan](#)

an>

Title : Need to solve the problems of agriculture sector in the country.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन (बेगूसराय) : सभापति महोदया, अभी 1 जुलाई, 2006 को प्रधान मंत्री ने विदर्भ के किसानों के लिए 3,750 करोड़ रुपये का एक पैकेज घोषित किया था। इस पैकेज का अभी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। यह केवल अभी कागज पर ही सिमट कर रह गया है। इसलिए विदर्भ में आत्महत्याओं का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और 52 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। पंजाब, हरियाणा जो खेती के मामले में सम्पन्न समझे जाते हैं, वहां का किसान भी कर्ज में डूबा है और आत्महत्याएं कर रहा है। 57,000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज पंजाब के किसान पर है। देश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनमें से 14 फीसदी से अधिक आत्महत्याएं किसानों द्वारा हैं। आज जरूरत है देश की कृषि को विकसित करने की, देश को खेती के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की, तभी हमारी खाद्य समस्या भी सुलझ पाएगी।

एक ओर देश खाद्य सामग्री की कमी से जूझ रहा है दूसरी ओर खेती की जमीन को अन्य उपयोगों में लिया जा रहा है। छोटी कार बनाने के लिए खेती की जमीन की जरूरत है, कृषि व्यापार के लिए खेती की जमीन चाहिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भी खेती की भूमि ली जा रही है। लगातार खेती की जमीन कम होती जाएगी तो उत्पादन बढ़ाने की बात केवल स्वप्न ही होगी। इसके अतिरिक्त खेती की अन्य समस्याएं भी हैं। कृषि उत्पादों के लिए बाजार, खेती की उत्पादन दर, सिंचाई की कमी, बीज का अभाव, मिट्टी की घटती उत्पादकता आदि।

मेरा आग्रह है कि सरकार एक राज्य या कुछ जिलों पर ध्यान केन्द्रित कर खेती की समस्या से देश को मुक्त नहीं कर पाएगी। उसे चाहिए कि सम्पूर्ण देश की खेती पर विचार करे और उसका समाधान करे।

